

भारत सरकार  
शिक्षा मंत्रालय  
उच्चतर शिक्षा विभाग  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1344  
उत्तर देने की तारीख-08/12/2025

एनईईटी उम्मीदवारों में आत्महत्या

†1344. श्री एस. जगतरक्षकन:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:

(क) एनईईटी परिणामों की घोषणा के बाद वगत तीन वर्षों के दौरान देश भर में एनईईटी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों सहित वद्व्यार्थियों द्वारा आत्महत्या के राज्यवर्ष-वार कतने मामले दर्ज कए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने एनईईटी उम्मीदवारों और मे डकल छात्रों के मान सक स्वास्थ्य संकट को समझने के लए कोई अध्ययनसर्वेक्षण कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे आत्महत्या को रोकने के लए एनईईटी अभ्यर्थियों को मनोवज्ञान संबंधी परामर्श, हेल्पलाइन सर्वस, तनाव प्रबंधन कार्यक्रम और करियर गाइडेंस देने के लए कोई सहायता प्रणाली बनाने की योजना बनाई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या केंद्र सरकार छात्रों की बार-बार होने वाली मान सक स्वास्थ्य चंताओं को देखते हुए मे डकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लए राज्यों को अ धक स्वायत्तता देने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (घ): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) पु लस द्वारा दर्ज आत्महत्या के मामलों से आत्महत्या संबंधी आंकड़े एकत्र करता है। देश में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या से संबंधित आंकड़ों का व्यापक वश्लेषण, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या (एडीएसआई) रिपोर्ट में प्रतिवर्ष प्रकाशित कया जाता है।

छात्र आत्महत्याओं का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा एडीएसआई रिपोर्ट में उपलब्ध है, जिसे <https://ncrb.gov.in/accidental-deaths-suicides-in-india-year-wise.html> पर देखा जा सकता है।

केन्द्र सरकार ने आत्महत्या की घटनाओं से बचने के लिए मानसिक और भावनात्मक कल्याण के लिए छात्रों, शिक्षकों और परिवारों को मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के लिए कई उपाय किए हैं।

- शिक्षा मंत्रालय ने दिनांक 10.07.2023 को उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में वदयार्थियों के भावनात्मक और मानसिक कल्याण के लिए एक व्यापक रूपरेखा भी प्रसारित की है, जिसमें संस्थानों से अनुरोध किया गया है कि वे इसे अपनी कार्यप्रणाली में सक्रिय रूप से शामिल करें और वदयार्थी समुदाय में आत्म विश्वास की भावना उत्पन्न करें।
- शिक्षा मंत्रालय द्वारा कोचिंग सेंटरों के वनियमन हेतु दिशानिर्देश दिनांक 16.01.2024 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उचित कानूनी रूपरेखा के माध्यम से वचार करने के लिए जारी किए गए हैं। इन दिशानिर्देशों में कई प्रमुख पहलुओं को शामिल किया गया है, जिनमें मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर बल देना, कोचिंग केन्द्रों में परामर्शदाताओं और मनोवैज्ञानिकों के सहयोग को प्राथमिकता देने का समर्थन करना, बैचों में अलगाव न करना, अभिनेतृओं का रखरखाव आदि शामिल हैं।
- शिक्षा मंत्रालय की एक पहल, मनोदर्पण, मानसिक और भावनात्मक कल्याण हेतु वदयार्थियों, शिक्षकों और परिवारों को मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के लिए गति वधियों की एक वस्तुतः श्रृंखला को शामिल करती है। इनमें - राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन शामिल है जो प्रशिक्षित परामर्शदाता के माध्यम से कॉल करने वालों को मार्गदर्शन प्रदान करती है और लाइव इंटरैक्टिव सत्र 'सहयोग' व वेबिनार 'परिचर्चा' जो सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वदयार्थियों सहित सभी हितधारकों के बीच मानसिक स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए नियमित रूप से आयोजित की जाती है। ये सत्र पीएम ई-वदया चैनलों पर प्रसारित किए जाते हैं और 'एनसीईआरटी के आधिकारिक' यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध हैं।
- देश में गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखभाल सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए वर्ष 2022 में एक राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया है। दिनांक 17.07.2025 की स्थिति के अनुसार, 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने राज्य भर में 53

टेली मान सक स्वास्थ्य सहायता और नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स (मानस) प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं। हेल्पलाइन नंबर पर 29,75,000 से अधिक कॉल का उत्तर दिया गया है। सरकार ने स्वास्थ्य से लेकर मानसिक विकारों तक के मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के लिए सहायता प्रदान करने के लिए टेली मानस मोबाइल एप्लिकेशन भी लॉन्च किया है।

- मानसिक विकारों की समस्या से निपटने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमएचएफडब्ल्यू) देश में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) कार्यान्वित कर रहा है। एनएमएचपी का जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) घटक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी) स्तरों पर डीएमएचपी के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई सुविधाओं में अन्य बातों के साथ-साथ आउट पैशेंट सेवाएं, मूल्यांकन, परामर्श/मनो-सामाजिक कार्यक्रमलाप, गंभीर मानसिक विकारों वाले व्यक्तियों के लिए निरंतर देखभाल और सहायता, दवाएं, प्रसार सेवाएं, एम्बुलेंस सेवाएं आदि शामिल हैं।
- उपरोक्त के अलावा, सरकार ने 1.81 लाख से अधिक उप स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में अपग्रेड किया है। इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में प्रदान की जाने वाली व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के तहत सेवाओं के पैकेजों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को जोड़ा गया है।

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) अधिनियम, 2019 की धारा 14 के अनुसार, देश के सभी चिकित्सा संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) प्रवेश एक समान प्रवेश परीक्षा के तौर पर आयोजित किया जाना है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 29 अप्रैल 2020 के मामले क्रिचियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर एसोसिएशन बनाम भारत सरकार एवं अन्य के निर्णय के माध्यम से सभी चिकित्सा संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु एनईईटी को एक समान प्रवेश परीक्षा के रूप में बरकरार रखा है और कहा है कि एकसमान प्रवेश परीक्षा आनुपातिकता की परीक्षा में उत्तीर्ण होता है और उचित है।

\*\*\*\*\*